भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 740

05.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता चलन

740 **श्री तिरुची शिवाः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है, जो कारों को चार्ज करने योग्य हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए फास्ट चार्जिंग सुविधा से सुसज्जित हैं;

(ख) निजी इलेक्ट्रिक वाहनों में रेंज एंग्जायटी को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम ई-ड्राइव योजना से विद्युत कारों को बाहर रखने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि पिछले दो वर्षों में किसी भी बस द्वारा पीएम ई-ड्राइव के तहत प्रस्तावित लाभों का उपयोग नहीं किया गया है;

(ड) यदि हाँ, तो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई समीक्षा या परामर्श किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) के लिए परियोजना लागू करने वाली एजेंसी बीएचईएल से प्राप्त सूचनानुसार 39,485 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जिनमें से 8,414 कारों के लिए तीव्र इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर हैं।

(ख) इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की दूरी संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के लिए गाइडलाइंस" जारी की हैं, जो बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशनों सहित संबद्ध और अंतरप्रचालन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क बनाने के लिए स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल बताते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाना एक लाइसेंसरहित गतिविधि है और निजी उद्यमी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(ग) भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम अधिसूचित की है। इसके अलावा, पीएलआई ऑटो और ऑटो कंपोनेंट स्कीम भी इलेक्ट्रिक कारों समेत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है।

(घ) और (ङ) पीएम ई-ड्राइव स्कीम 29/09/2024 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत, ई-बसों की खरीद, कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर आधारित एग्रीगेशन मॉडल के ज़रिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा की जाती है। फेज़ I में, पाँच शहरों को 10,900 ई-बसें आवंटित की गई हैं, और इन 10,900 ई-बसों के लिए ई-बस प्रचालक के चयन के लिए बोली 14.11.2025 को खोली गई हैं। इसके अलावा, ई-बसों के आवंटन के फेज़ II के तहत और 2,900 ई-बसें आवंटित की गई हैं।

(च) वैसे तो, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। हालाँकि, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए नीचे दी गई कई स्कीमें लागू कर रही है:-

i. **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों समेत एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है, जिसका बजट 25,938 करोड़ रुपए है।

ii. **नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 9 जून, 2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएलआई स्कीम को अधिसूचित किया। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावॉट एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम बनाना है।

iii. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह स्कीम 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित की गई है। इस स्कीम में ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस जैसी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्थन शामिल है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन भी इस स्कीम में शामिल है।

iv. **पीएम ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) स्कीम:** 28.10.2024 को अधिसूचित की गई इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपए है और इसका

उद्देश्य 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में मदद करना है। इस स्कीम का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (पीटीए) के चूक करने पर ई-बस संचालकों को भुगतान सुरक्षा देना है।

v. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम(एसपीएमईपीसीआई)** 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था ताकि भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए निवेश करने होंगे और तीसरे वर्ष के आखिर में न्यूनतम 25% तथा पांचवें वर्ष के अंत में 50% घरेलू मूल्यवर्धन हासिल करना होगा।

****